'पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल को 34 माह में ही कई गुना पीछे छोड़ा'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण व पशुपालन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की

जयपुर, 22 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण, पशुपालन, आधारभूत ढांचे और राजस्व ग्रामों के विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति दी है। योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पहले 34 माह के साथ-साथ पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को कई गुना तक पीछे छोड़ बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

भाजपा सरकार ने 34 माह में 1 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नहरी तंत्र से सृजित सिंचाई सुविधा का विस्तार किया है, जबकि कांग्रेस सरकार के पहले 34 माह में यह आंकड़ा 35 हजार 909 हेक्टेयर तथा पांच वर्ष में 52 हजार 182 हेक्टेयर था। इस प्रकार वर्तमान सरकार ने कांग्रेस के पांच वर्ष के कार्यकाल की तुलना में लगभग पौने तीन गुना अधिक क्षेत्र में नहरी सिंचाई सुविधा सृजित की है।

जल संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार ने ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया है। इन प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से अब तक 3 लाख 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित किया गया है। वहीं, कांग्रेस सरकार के 34 महीनों में 29 हजार 609 हेक्टेयर और पांच वर्ष में 1 लाख 83 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

■ राज्य सरकार ने ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया। इन प्रणालियों की स्थापना से अब तक 3 लाख 10 हजार हेक्टेयर भूमि को लाभांवित किया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पहले 34 माह में 29 हजार 609 हेक्टेयर तथा 5 साल में 1 लाख 83 हजार हेक्टेयर क्षेत्र ही लाभांवित हुआ था।

राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने पशु चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में भाजपा सरकार में 55 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन हुआ है, जबकि कांग्रेस सरकार के 34 माह में इस श्रेणी में एक भी क्रमोन्नयन नहीं हुआ। इसी प्रकार, वर्तमान सरकार 117 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत कर चुकी है, जबकि कांग्रेस सरकार ने पहले 34 माह में केवल तीन ही पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया था।

राजेन्द्र राठौड़ के पुत्र व पुत्रवधु ने नामांकन भरा

चूरू, 22 अक्टूबर। जिले में पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में गुरूवार को भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह व पुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ ने जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व, भाजपा प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए राठौड़ के निवास पर एक सभा का आयोजन किया।

■ जिला परिषद सदस्य का नामांकन भरने से पहले राठौड़ के निवास पर सभा आयोजित हुई।

इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष, राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि पंचायती राज चुनाव ग्रामीण विकास और समस्याओं के समाधान के लिए अहम हैं। उन्होंने प्रत्याशियों से जनसंपर्क बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने पर बल दिया। इस दौरान विधायक हरलाल सहारण ने ग्रामीण विकास, सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कार्यकर्ताओं से पार्टी प्रत्याशियों के साथ मिलकर चुनावी गतिविधियों को गति देने की अपील की।

हर दिन 28 लाख बैरल क्रूड ऑयल भारत आ रहा है

पश्चिम एशिया से तेल आयात युद्ध से पहले के स्तर पर पहुंच गया है

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। सितंबर में पश्चिम एशिया से भारत का कच्चा तेल आयात खाड़ी युद्ध के पूर्व स्तर पर पहुंच गया। वहीं, चीन के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल खरीद कम कर दी है।

पश्चिम एशिया के उत्पादकों और व्यापारियों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते तेल की आपूर्ति बढ़ा दी है, जिससे ईरान युद्ध के कारण पैदा हुई आपूर्ति की कमी दूर हुई है।

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत ने खाड़ी युद्ध के शुरू होने के बाद, पश्चिम एशिया से आपूर्ति घटने की भरपाई के लिए रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया था।

शिपिंग ट्रैकिंग डाटा के अनुसार, सितंबर में पश्चिम एशिया से भारत का कच्चे तेल का आयात बढ़ कर लगभग 28 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जो फरवरी के बाद का सबसे उच्च स्तर है। यह अगस्त के मुकाबले 32 प्रतिशत अधिक है।

कुल आयात में खाड़ी देशों के तेल की हिस्सेदारी लगभग 54 प्रतिशत रही। इसके विपरीत, सितंबर में रूस से तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत घटकर 18 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। भारत की कुल तेल खरीद में रूस की हिस्सेदारी 46.6 प्रतिशत से घटकर 33.5 प्रतिशत पर आ गई है। एक भारतीय रिफाइनिंग सूत्र ने बताया कि आने वाले महीनों में भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूस से तेल की खरीद कम रहने की संभावना है, क्योंकि अब रूसी तेल की लागत पश्चिम एशिया, खासकर इराक, से आने वाले तेल के बराबर हो गई है।

■ सूत्रों ने बताया कि रूस से तेल आयात 14 प्रतिशत घटकर 18 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है।

इतना ही नहीं पश्चिम एशिया से आपूर्ति बढ़ने के बाद रूस से आने वाला कच्चा तेल भी अब उतना किफायती नहीं रह गया है, जितना पहले था। ऐसे में रिफाइनरियां पश्चिम एशिया से मिलने वाले सस्ते कच्चे तेल की खरीद को प्राथमिकता देंगी, क्योंकि इस क्षेत्र से तेल आने में समय कम लगता है।

तमिलनाडु के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार ने वाहन खरीद की निर्धारित सीमा में हर साल पांच प्रतिशत वृद्धि का भी प्रविधान किया है। नियमों के मुताबिक, पद छोड़ने, कार्यकाल पूरा होने या अयोग्य घोषित किए जाने पर मंत्रियों को सरकारी वाहन लौटाना होगा।

पंजाब में दोनों अकाली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें पंजाब मामलों के प्रभारी सतीश पूनिया भी शामिल हैं, "पुनर सुरजीत" गुट के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। इससे पहले की रिपोर्टों में भाजपा और एसएडी के बीच सीटों के बंटवारे पर शुरुआती बातचीत की बात कही गई थी। अगस्त में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई सुखबीर बादल की मुलाकात को भी दोनों पक्षों के बीच जमी बर्फ पिघलने (बातचीत की शुरुआत) के रूप में देखा गया था। सीटों का बंटवारा ही सबसे बड़ा अटका हुआ मुद्दा है। कहा जा रहा है कि भाजपा अपनी पारंपरिक 23 सीटों से कहीं ज्यादा सीटें मांग रही है। इसके पीछे वे 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने बेहतर प्रदर्शन का हवाला दे रहे हैं (भाजपा का वोट शेयर लगभग 18-19 प्रतिशत रहा था, जबकि एसएडी का 13-14 प्रतिशत था)।

सूत्रों का कहना है कि इसकी औपचारिक घोषणा "कभी भी" हो सकती है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक समय-सीमा तय नहीं हुई है और दोनों ही दल अभी सार्वजनिक रूप से काफी सतर्कता बरत रहे हैं। अगर इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दे दिया जाता है, तो सत्ताधारी "आप" और कांग्रेस के साथ होने वाले संभावित त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी।

भाजपा के शहरी और हिंदू आधार को अकाली दल के ग्रामीण और "पंथी" समर्थन के साथ मिलाने से, "आप" के खिलाफ सत्ता-विरोधी वोटों को एकजुट किया जा सकेगा। इससे वोटों का वह तीन-तरफा बंटवारा भी रुक जाएगा, जिसका फायदा पहले सत्ताधारी पार्टी को मिलता रहा है।

भारतीय नागरिकों की नाव पर हूती विद्रोहियों का हमला

यमन के सशस्त्र बल ने सभी 14 भारतीयों को बचाया

सना (यमन), 22 अक्टूबर। यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि लाल सागर में 14 भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक नाव को सऊदी अरब ने निशाना बनाया, जिसके बाद यमन के सशस्त्र बलों ने अभियान चला कर इन भारतीय नागरिकों को बचाया है। हालांकि, हूती के इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है और न ही संगठन ने इसके बारे में विस्तार से बताया कि अगर भारतीय नागरिकों की नाव को निशाना बनाया गया और उन्हें बचाया गया तो इन्हें कहां ले जाया गया और उनकी हालत कैसी है।

चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क (सीजीटीएन) के मुताबिक, हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि लाल सागर में जूकर द्वीप के पास भारतीय नागरिकों वाली नाव को सऊदी अरब ने निशाना बनाया। नाव पर सवार सभी 14 भारतीयों को यमन के सशस्त्र बलों ने अभियान चलाकर बचा लिया है।

■ चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के अनुसार हूती विद्रोहियों ने हमले का दावा किया पर इस दावे की पुष्टि नहीं हुई तथा उस संगठन ने विस्तृत सूचना भी नहीं दी।

हूती सैन्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने लाल सागर में बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के पास जुकार द्वीप के निकट एक भारतीय नाव को निशाना बनाया, जिस पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उन्हें बचाया जा रहा है और संगठन की तरफ से आगे की जानकारी दी जाएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि सऊदी दुश्मन की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय नौवहन (शिपिंग) के लिए खतरा पैदा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सऊदी दुश्मन को ऐसी गैर-जिम्मेदाराना हरकतें करने से रोकना चाहिए।

क्राइम ब्रांच ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहीं घुसने और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप शामिल हैं। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरी एफआईआर में सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने, उन पर हमला करने और घटना के दौरान पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। बुधवार को दास और रांका तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी। ये दोनों नेता 14 अक्टूबर से हिरासत में थे। उन पर यह कार्रवाई शांति भंग होने की आशंका और पहले भरे गए शांति बॉन्ड (पीस बॉन्ड) के उल्लंघन के चलते शुरू की गई थी। जब उन्होंने 50,000-50,000 रुपये के निजी बॉन्ड और ज़मानत पेश की, तब मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, उन्होंने शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का लिखित आश्वासन भी दिया।

पाकिस्तान, तुर्की, कतर व इंडोनेशिया के बीच "बद्र" रक्षा समझौता सम्पन्न

दोहा में हुए इस समझौते से चारों देशों में सैन्य उत्पाद, रक्षा तकनीक, प्रशिक्षण अनुसंधान की संभावना बढ़ जाएगी

दोहा, 22 अक्टूबर। पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने और अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को 'बद्र मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (समझौता) पर हस्ताक्षर किए। कतर की राजधानी दोहा में हुए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सैन्य उत्पादन, रक्षा तकनीक, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के क्षेत्र में चारों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

पाकिस्तान की उर्दू टेलीविज़न चैनल दुनिया न्यूज तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया जिओ न्यूज के मुताबिक, तुर्किये के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता चारों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी को गहरा करने और उनकी औद्योगिक क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से प्रत्येक देश की रक्षा उत्पादन संबंधी विशेषज्ञता का लाभ उठाने, संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने और मित्र देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

■ यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में भारी तनाव व्याप्त है।

समझौते पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम में चारों देशों के वरिष्ठ रक्षा प्रतिनिधि शामिल हुए।

'बद्र' समझौते के तहत, चारों देश रक्षा क्षेत्र में अपनी क्षमताओं और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए सहयोग का ढांचा विकसित करेंगे।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनका देश भरोसेमंद साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग मजबूत करने को महत्व देता है। उन्होंने इस समझौते को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति चारों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय तनाव को लेकर कई देश अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। चारों देशों के बीच सहयोग से रक्षा तकनीक, सैन्य प्रशिक्षण और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं।

मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर 12 नवम्बर को चुनाव

भोपाल, 22 अक्टूबर। राज्यसभा से डॉ. एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद, मध्य प्रदेश से रिक्त हुई एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया। इस सीट पर 12 नवंबर को मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी।

डॉ. एल. मुरुगन सरकार में मंत्री भी थे। वे 3 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बने थे, उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था, लेकिन उन्होंने 14 अक्टूबर को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के साथ ही राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट रिक्त हो गई। इस रिक्त सीट को भरने के लिए आज निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, उपचुनाव की अधिसूचना 26 अक्टूबर को जारी होगी। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 5 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इस सीट पर 12 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद, उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

■ केन्द्रीय मंत्री मुरुगन के इस्तीफे के कारण यह सीट खाली हुई थी

मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें आठ पर भाजपा और तीन पर कांग्रेस के सांसद थे। एल मुरुगन के इस्तीफा के बाद भाजपा के कोटे की एक सीट रिक्त हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं। यदि सभी विधायक मतदान करें और कोई मत अवैध न हो, तो एक राज्यसभा सीट के चुनाव में जीत के लिए आवश्यक मतों का कोटा 116 होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा के 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 65 और भारत आदिवासी पार्टी का एक विधायक है। ऐसे में उपचुनाव में भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है।

नेहा बोरा की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शंकरनारायणन ने कहा कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा ने बोरा की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कानून हमें धारा 126 और 130 को एक साथ लागू करने की अनुमति देता है। याचिका में नेहा बोरा ने दस हजार रुपये के निजी मुचलका भरने और शांति बनाए रखने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी है।

प्र.मंत्री मोदी ने अमित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तीन वर्षों के आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान 4,839 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, 2,218 को गिरफ्तार किया गया और 706 माओवादी मुठभेड़ों में मारे गए।

उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा के कारण बस्तर विकास से वंचित रहा है। अब इस क्षेत्र के लोगों को आवास, गैस कनेक्शन, पीने का पानी और बीमा जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद देश को आधिकारिक रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त घोषित किया जाएगा।

एक बड़ी कार्रवाई मई 2025 में हुई थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 27 माओवादियों को मार गिराया था। इनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी शामिल थे। तीन दशकों में यह पहली बार हुआ था, जब इस स्तर के किसी नेता को मार गिराया गया हो।

उत्तराखंड में एक सदी से लॉक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंततः, यदि जमा हुआ तनाव उस प्रतिरोध को पार कर जाए जो फॉल्ट (चटटानों की दरार) को अपनी जगह पर रोके हुए है, तो चट्टानें अचानक खिसक सकती हैं, और ऊर्जा भूकंप के रूप में बाहर निकल सकती है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्तराखंड के नीचे स्थित मुख्य फॉल्ट, जिसे "मेन हिमालयन थ्रस्ट" कहा जाता है, पूरी तरह से लॉक्ड है, जकड़ा हुआ है। उनकी गणना के अनुसार, इस फॉल्ट पर हर साल लगभग 18 मिलीमीटर का "मूवमैंट डैफिसिट" (गति में कमी) जमा हो रहा है। आसान शब्दों में कहें तो भारतीय प्लेट लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस गति का एक बड़ा हिस्सा दरार के किनारे धीरे-धीरे खिसकने के बजाय, रुका हुआ है।

यह "लॉक्ड" हिस्सा अनुमानित रूप से करीब 115 किलोमीटर चौड़ा है, जो एक ऐसा बड़ा क्षेत्र बनाता है, जहाँ तनाव जमा हो सकता है।

अध्ययन में जमीन की ऊंचाई में होने वाले बदलावों का भी पता चला। सैटेलाइट उपग्रह से प्राप्त रडार आंकड़ों के अनुसार, कुछ इलाकों में जमीन हर साल 4 से 6 मिलीमीटर तक ऊपर उठ रही है। जमीन में होने वाले ये बदलाव बेहद छोटे हैं और आमतौर पर लोगों को महसूस नहीं होते। लेकिन जब अत्याधुनिक उपकरणों से बार-बार मापा जाता है, तो इससे, धरती में बहुत नीचे क्या हो रहा है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

जमीन की पार्श्व (बगल की) गति और ऊँचाई में होने वाले बदलावों के आंकड़ों को मिलाकर शोधकर्ताओं ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया, जो देखे गए पैटर्न से काफी हद तक मेल खाता है। उनके निष्कर्ष इस बात को और पुख्ता करते हैं कि यह "फॉल्ट" पूरी तरह से "लॉक्ड" है और इस क्षेत्र के नीचे लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है।

उत्तराखंड मध्य हिमालय के उस हिस्से में स्थित है, जिसे वैज्ञानिक लंबे समय से बड़े भूकंपों का संभावित स्रोत मानते रहे हैं। इस क्षेत्र के बड़े हिस्सों में 200 साल से अधिक समय से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, हालांकि दरार का वास्तविक विस्तार कितना है और इससे कितना खतरा पैदा हो सकता है, इस पर अभी भी वैज्ञानिक अध्ययन जारी हैं।

लंबे समय तक कोई बड़ा भूकंप न आने का मतलब यह नहीं है कि अगला भूकंप कब आएगा, यह तय हो गया है। और न ही इसका मतलब यह है कि पहाड़ों के नीचे हर जगह एक समान गति से दबाव बढ़ रहा है।

फिर भी, ये निष्कर्ष बताते हैं कि उत्तराखंड और उससे सटे मैदानी इलाकों में भूकंप से बचाव की तैयारियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इन इलाकों में बड़ी आबादी, तेजी से फैलते शहर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे मौजूद हैं, जिन्हें किसी बड़े भूकंप के दौरान भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

इमारतों, सड़कों, पुलों, बांधों और अन्य महत्वपूर्ण ढांचों का निर्माण और रखरखाव इस क्षेत्र में भूकंप के खतरे को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। आपातकालीन योजनाएं बनाना और लोगों को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है।

इस शोध का मुख्य संदेश स्पष्ट है: उत्तराखंड की धरती के नीचे दबाव लगातार जमा हो रहा है, जो भविष्य में एक शक्तिशाली भूकंप का कारण बन सकता है। लेकिन विज्ञान अभी यह नहीं बता सकता कि ऐसा भूकंप कब आएगा। इस धीमी और काफी हद तक अदृश्य प्रक्रिया को समझना जरूरी है, ताकि क्षेत्र के सबसे गंभीर दीर्घकालिक प्राकृतिक खतरों में से एक से निपटने की तैयारी की जा सके।

अमेरिका ने सऊदी अरब से राजनयिक वापस बुलाए

रियाद, 22 अक्टूबर। हूती लड़ाकों के हमलों के बीच, अमेरिका ने अपने ज्यादातर राजनयिकों और उनके परिवारीजनों को अविलंब सऊदी अरब छोड़ने के लिए कहा है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब के अतिरिक्त अरब जगत के अन्य देशों में स्थित अपने दूतावासों में भी राजनयिकों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया है। ऐसा दूतावासों पर हमले की आशंका और अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाए जाने के खतरे के चलते किया गया है। अमेरिका ने यह निर्णय सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल ठिकानों पर लगातार हो रहे हूती के हमलों को देखते हुए लिया है। अमेरिका ने फरवरी में ईरान पर हमले के बाद क्षेत्र के कई देशों में अपने राजनयिकों की संख्या लगातार कम की है।

आने वाले दिनों में यह संख्या और कम किए जाने के संकेत हैं। चार अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अरब देशों में स्थित दूतावासों में गैरजरूरी अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारीजनों को अमेरिका लौटने के लिए कहा गया है।

सऊदी अरब के एक और एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का हमला

एक की मौत, आठ घायल, एयरपोर्ट के नुकसान का आंकलन कार्य जारी

रियाद, 22 अक्टूबर। सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में दम्माम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार शाम हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। यह जानकारी सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दी है।

अथॉरिटी के बयान में कहा गया कि घायलों की हालत मामूली से लेकर गंभीर तक है। एयरपोर्ट को हुए भौतिक नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

हमला कैसे हुआ, इसका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा प्रोजेक्टाइल से सऊदी एयरपोर्ट्स पर बार-बार हमले किए जा रहे हैं।

यह हमला क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, जहां हूती हमलों से सऊदी अरब के कई एयरपोर्ट प्रभावित हो चुके हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को कहा कि वाशिंगटन ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास के गैर-जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोही द्वारा सऊदी अरब पर लगातार घातक हमले किए जा रहे हैं।

■ पिछले कुछ दिनों में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कई सऊदी हवाई अड्डों पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया है।

यह घटना तब सामने आई, जब एक राजनयिक सूत्र ने एएफपी को बताया कि खाड़ी राज्य में स्थित अमेरिकी दूतावास से सभी अमेरिकी कर्मचारियों और उनके परिवारों को चले जाने का आदेश दिया गया है।

सऊदी अरब के शैबा ऑयलफील्ड पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक घायल हो गया है। भारत के सऊदी अरब स्थित दूतावास ने इसकी पुष्टि की है।

दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दूतावास को पता चला है कि आज शैबा ऑयलफील्ड पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक घायल हुआ है। हम सऊदी अधिकारियों के संपर्क में हैं और आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। घायल भारतीय नागरिक को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

शैबा ऑयलफील्ड सऊदी अरब का एक प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र है। क्षेत्र में हाल के दिनों में हूती हमलों और तनाव के बीच यह घटना हुई है। दूतावास घायल भारतीय की स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यक सहायता सुनिश्चित कर रहा है।

दिल्ली नगर निगम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुई। आप पार्षदों का आरोप है कि सात महीने बीतने के बाद भी दो करोड़ रुपये के घोषित फंड में से सिर्फ 50 लाख रुपये ही मिले हैं।

महापौर कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सदन में दिल्ली के प्रदूषण और सफाई व्यवस्था पर आधे घंटे की चर्चा होनी थी। त्योहारों से पहले सफाई के इंतजाम बेहतर करने को लेकर भी फैसले लिए जाने थे। महापौर ने आरोप लगाया कि आप पार्षदों ने हंगामा करके चर्चा नहीं होने दी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031-32,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422-23, जालौर। फैक्स: 02973-226424, हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908